GEO IAS

It's about quality

12-13 May 2024

जियो दैनिक

डेली करंट अफेयर्स

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET

Date: 12-13 May 2024

Important News Articles

1. अमेरिकी एआई पर चल रहे हैं रूस के किलर लैंसेट ड्रोन'- टाइम्स ऑफ इंडिया
2. सशस्त्र बलों की एकीकृत कमांड संरचना योजना में वाइस सीडीएस, डिप्टी सीडीएस को स्पष्ट भूमिकाएं दी गई - द इंडियन एक्सप्रेस
3. सरकार चीन सीमा पर सड़कों पर प्रति किमी ₹2 करोड़ खर्च करेगी- द हिन्दू
4. आमूलचूल कदम (शिफ्टिंग गियर) : अर्जेंटीना सौदे के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलियाई लिथियम ब्लॉकों को निशाना बनाया- द हिंदू
5. मई, जून में चरम बिजली की मांग को पूरा करने के उपाय - द हिंदू
6. अतिक्रमण और भूमि परिवर्तन से राष्ट्रीय राजधानी के फेफड़े 'दिल्ली रिज (चोटी)' को खतरा - द हिंदू
7. उच्च न्यायालय पैनल ने मेघालय में कोयला खनन क्षति को निम्न करने की खराब प्रगति पर प्रकाश डाला - द हिंदू
8. वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में जंगल की आग प्रबंधन के लिए 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और नियंत्रित आग' के लिए वार्ता - डाउन टू अर्थ

Editorials, Gists and Explainers

9. डिजीलॉकर क्या है और क्या यह आपके डेटा और दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखता है? - हिन्दू
10. भारत- EFTA व्यापार सौदे से निवेश का सबक - द हिंदू

Quick Look

1. अरोरा
2. डेडबॉट्स
3. कावासाकी रोग
4. सशस्त्र बलों का रंगमंचीकरण

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. अमेरिकी एआई पर चल रहे हैं रूस के किलर लैंसेट ड्रोन'- टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- द्वितीय विश्व युद्ध

समाचार:
- यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में, रूस लैंसेट कामिकेज़ ड्रोन का उपयोग कर रहा है, जिसमें अमेरिकी एआई तकनीक शामिल है

मुख्य विचार
- छोटे, विस्फोटक ड्रोन जिन्हें **कामिकेज़ ड्रोन और स्विचब्लेड ड्रोन** भी कहा जाता है,
- इससे टैंक या सैनिकों जैसे दुश्मन के ठिकानों पर उड़ाया जा सकता है,
- द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी पायलटों के नाम पर, जिन्होंने इसी तरह के आत्मघाती हमले किए थे, ये आधुनिक ड्रोन सुरक्षा को दरकिनार करने और लक्ष्यों पर हमला करने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं।
- **रडार से बचने और चेहरे की पहचान** जैसी उन्नत सुविधाएँ कुछ कामिकेज़ ड्रोनों को मानव नियंत्रण के बिना हमला करने की अनुमति देती हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका इस तकनीक में अग्रणी है, लेकिन रूस, चीन, इज़राइल, ईरान और तुर्की जैसे अन्य देश भी कामिकेज़ ड्रोन विकसित कर रहे हैं।
- लैंसेट-3 ड्रोन एक विशिष्ट प्रकार का कामिकेज़ ड्रोन है जिसे अनियंत्रित युद्ध सामग्री के रूप में जाना जाता है।
- इसमें शक्तिशाली **एनवीडिया जेट्सन TX2 AI चिप** का उपयोग किया गया है, जो इसे बहुत कुशल बनाता है।

सामान्य अध्ययन III

2. सशस्त्र बलों की एकीकृत कमांड संरचना योजना में वाइस सीडीएस, डिप्टी सीडीएस को स्पष्ट भूमिकाएं दी गई - द इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके कार्यक्षेत्र।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सीडीएस
- सीमा सुरक्षा

समाचार:
- सशस्त्र बल एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु:
- **वाइस सीडीएस,** संभवतः जनरल रैंक का अधिकारी होगा, जो रणनीतिक योजना, क्षमता विकास और खरीद-संबंधी मामलों की देखभाल करेगा।
- **डिप्टी सीडीएस**, संभवतः लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होगा, संचालन, खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार होगा और सिनेमाघरों के बीच संपत्ति के आवंटन का समन्वय करेगा।
- हालाँकि संगठनात्मक संरचना योजना को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद बेहतर बनाया जा सकता है,
- इससे **थिएटर कमांड** का निर्माण होगा, (जयपुर, लखनऊ, कोयंबटूर में थिएटर कमांड के लिए संभावित स्थान)
- समग्र योजना तीन शत्रु-आधारित थिएटर कमांड स्थापित करने की है -
  - एक पाकिस्तान की ओर,
  - एक चीन की ओर, और
  - देश की तटीय सीमाओं के बाहर समुद्री खतरों से निपटने के लिए एक समुद्री थिएटर कमांड।

3. सरकार चीन सीमा पर सड़कों पर प्रति किमी ₹2 करोड़ खर्च करेगी- द हिन्दू

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन किया जाना

प्रीलिम्स टेकअवे
- वी.वी.पी
- भारत-चीन सीमा

समाचार:
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत चीन सीमा के आस- पास बनने वाली प्रत्येक कि.मी. सड़क पर सरकार द्वारा ₹2 करोड़ से अधिक खर्च करने की संभावना है।

मुख्य विशेषताएं:
- पिछले पांच महीनों में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वीवीपी के तहत 113 सड़कों को मंजूरी दी है।
- चीन की सीमा पर कम से कम 168 गांव ऐसे हैं जहां कोई सड़क संपर्क नहीं है।
- मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जीपीएस-सक्षम वाहन ट्रैकिंग उपकरण स्थापित करके निर्माण गतिविधि की निगरानी करने को भी कहा है।
- वीवीपी के तहत सड़क कार्यों के निष्पादन के दौरान लगी प्रमुख मशीनरी और उपकरणों में जीपीएस सिस्टम की स्थापना राज्य सुनिश्चित करेंगे

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी):
- कार्यक्रम की मंजूरी- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 फरवरी, 2023 को
- वीवीपी के घोषित प्रमुख उद्देश्यों में से एक सीमा पर रहने वाली आबादी में प्रवास को रोकना है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए वीवीपी के लिए आवंटित ₹4,800 करोड़ के बजट में से आधे से अधिक, यानी लगभग ₹2,500 करोड़ सड़क निर्माण पर खर्च किए जाने हैं।

4. आमूलचूल कदम (शिफ्टिंग गियर) : अर्जेंटीना सौदे के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलियाई लिथियम ब्लॉकों को निशाना बनाया- द हिंदू

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लिथियम
- भारत-ऑस्ट्रेलिया सम्बन्ध

समाचार:
- भारत,ऑस्ट्रेलिया में **लिथियम ब्लॉक** सुरक्षित करने जा रहा है क्योंकि उसका लक्ष्य राज्य के स्वामित्व वाली **खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** के माध्यम से "इस वित्तीय वर्ष के भीतर संभावित" सौदे को अंतिम रूप देना है।

मुख्य विशेषताएं:
- ऑस्ट्रेलिया में **2 लिथियम ब्लॉक** और **3 कोबाल्ट ब्लॉक** पर चर्चा चल रही है।
- उचित परिश्रम प्रक्रिया में संभावित अन्वेषण स्थलों का मूल्यांकन और महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की संभावना का आकलन करना शामिल होगा।
- अर्जेंटीना की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में अधिग्रहण थोड़ा महंगा होगा, जिसके तहत वित्तीय आवश्यकताओं और विवरणों पर काम किया जा रहा है।
- भारत का यह प्रयास बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन सुरक्षित करने और चीनी आयात पर निर्भरता को कम करने की भारत की वर्तमान आवश्यकता को निरुपित करता है।
  - लिथियम भारत के हरित ऊर्जा में परिवर्तन और इसके **कार्बन पदचिह्न** में कमी का आधार बना हुआ है।
  - **'सफेद सोना'** कहे जाने वाले लिथियम का व्यापक उपयोग ऊर्जा भंडारण समाधानों में होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (**ईवी**), कार बैटरी और मोबाइल फोन आदि शामिल हैं।
- देश की अधिकांश लिथियम ज़रूरतें आयात पर निर्भर हैं।
  - वाणिज्य मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, **वित्तीय वर्ष 2023** में लिथियम का आयात **₹266 करोड़** का था।
- इस साल की शुरुआत में, भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के लिए अपना पहला विदेशी अधिग्रहण किया, जिनके नाम हैं- कोर्टाडेरा-I, कोर्टाडेरा-VII, कोर्टाडेरा-VIII, कैटियो-2022-01810132 और कोर्टाडेरा-VI।

5. मई, जून में चरम बिजली की मांग को पूरा करने के उपाय - द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि

प्रीलिम्स टेकअवे
- नवीकरणीय ऊर्जा
- उदय

समाचार:
- बिजली मंत्रालय ने इस गर्मी के मौसम में लगभग **260 गीगावॉट** की सर्वाधिक मांग का अनुमान लगाया है

मुख्य विशेषताएं:
- सरकार ने मई और जून में क्रमशः अनुमानित **235 गीगावॉट** और **240 गीगावॉट** बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मांग और बढ़ेगी क्यों कि जून 2024 तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान होने की संभावना है,
  - यह देखते हुए कि बिजली आपूर्ति एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है अतः अप्रैल और मई में भारत के आम चुनावों के कारण वितरण इकाइयों को आपूर्ति व्यवधानों को कम करने की सलाह दी जाती है।
- उपायों के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि 'बिजली उत्पादन के लिए पूरी क्षमता उपलब्ध कराने के लिए कोयला आधारित इकाइयों के अलावा गैस आधारित बिजली संयंत्रों को **धारा 11** के तहत निर्देश जारी किए गए हैं।'
  - जलविद्युत उत्पादन के अनुकूलन ने मई और जून के दौरान मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 4 गीगावॉट उपलब्ध कराया है।
  - थर्मल पावर प्लांटों के नियोजित रखरखाव और जबरन कटौती को कम करने से गर्मी के मौसम के लिए अतिरिक्त 5 गीगावॉट उपलब्ध हो गया है।
  - इसके अलावा, मई और जून के दौरान पवन से उत्पन्न बिजली 4 गीगावॉट से 5 गीगावॉट तक बढ़ने की उम्मीद है।

6. अतिक्रमण और भूमि परिवर्तन से राष्ट्रीय राजधानी के फेफड़े 'दिल्ली रिज (चोटी)' को खतरा - द हिंदू

प्रासंगिकता: पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और उसमे गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

प्रीलिम्स टेकअवे
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- दिल्ली रिज (चोटी)

समाचार:
- एक **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी)** की रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील दिल्ली रिज क्षेत्र के **308 हेक्टेयर** से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है और **अन्य 183 हेक्टेयर** को **"गैर-वानिकी उद्देश्यों"** के लिए "**डायवर्ट**" किया गया है.

दिल्ली रिज (चोटी) की मुख्य विशेषताएं:
- यह प्राचीन अरावली पहाड़ियों का अंतिम छोर है, जो लगभग **1,500 मिलियन वर्ष पुराना** है
- **क्षेत्र-** दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है।
- आधिकारिक आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का हरित क्षेत्र "दिल्ली रिज" 5% अतिक्रमण और 4% डायवर्जन के कारण खतरे में है।
- हालाकि वास्तविक अतिक्रमण इससे कहीं अधिक हो सकता है और जिसका अनुमान दिल्ली रिज की पूरी सीमा को **जियो-टैग** किए गए स्तंभों द्वारा सुरक्षित किए जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

दिल्ली रिज के समक्ष चुनौतियाँ:
- दिल्ली रिज,एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और भौगोलिक विशेषता से युक्त है, जो हालिया असंख्य चुनौतियों से घिरे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है।
  - तेजी से होने वाला शहरीकरण
  - दिल्ली की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि और
  - संसाधनों का अंधाधुंध दोहन.

7. उच्च न्यायालय पैनल ने मेघालय में कोयला खनन क्षति को निम्न करने की खराब प्रगति पर प्रकाश डाला - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- रैट होल कोयला खनन
- एनजीटी

समाचार:
- मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक पैनल ने पूर्वोत्तर राज्य में **रैट-होल कोयला खनन** से क्षतिग्रस्त पर्यावरण को बहाल करने में प्रगति की कमी को चिह्नित किया है।

मुख्य विशेषताएं:
- न्यायमूर्ति ब्रोजेंद्र प्रसाद कटाके ने **मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना निधि (MEPRF)** के गैर-उपयोग प्रकृति को रेखांकित किया।
- वस्तुतः रैट-होल खनन में इतनी बड़ी सुरंगें खोदना शामिल है कि कोई व्यक्ति रेंगकर कोयला निकाल सके।
  - अप्रैल 2014 में रैट-होल कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- पैनल ने कहा कि मेघालय की खनन प्रभावित पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है-
  - इसमें कहा गया है कि खदानों के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोग, खदान के गड्ढों से लगातार एसिड की निकासी के कारण पीड़ित हैं, जिन्हें अभी तक बंद नहीं किया गया है।
- समिति ने यह भी कहा कि कोक ओवन, फेरोलॉय और सीमेंट कारखानों के कैप्टिव बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोयले के स्रोत का अंकेक्षण (ऑडिट) चल रहा है और तीन सप्ताह के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
- पैनल ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामित डिपो में पुनर्मूल्यांकन या पुन: सत्यापित आविष्कारित कोयले के परिवहन के पूरा होने के तुरंत बाद **ड्रोन सर्वेक्षण** (अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए) आयोजित करने की सिफारिश की।

8. वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में जंगल की आग प्रबंधन के लिए 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और नियंत्रित आग' के लिए वार्ता - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- UNSPF
- UNFF

समाचार:
- 8 मई, 2024 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFF-19) के 19वें सत्र में प्रतिनिधियों ने उच्च-स्तरीय के मसौदा प्रपत्रों पर अनौपचारिक वार्ता में प्रवेश किया।

हालिया घटनाक्रम-
- **घोषणा UNFF-19**, **6-10 मई, 2024** को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था।
- 19वें सत्र में, UNFF का लक्ष्य वनों की रक्षा के लिए देशों से मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ हासिल करना था।
- ये प्रतिबद्धताएं UNSPF (वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना-2030) को लागू करने के लिए विशिष्ट कार्यों का मार्गदर्शन करेंगी

UNFF(वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम)
- **स्थापना** - वर्ष 2000,
- **कार्य**- UNFF एक वैश्विक चर्चा मंच है जो दुनिया के जंगलों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए समर्पित है।
- UNFF एक समावेशी संरचना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश भाग लेते हैं।
- भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है.
- हर साल, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और वन विशेषज्ञ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलते हैं।
- सदस्य वन प्रबंधन पर तकनीकी चर्चा और वन संरक्षण के लिए नीतिगत निर्णयों के बीच बारी-बारी से चर्चा करते हैं।

UNSPF(The United Nations Strategic Plan for Forests)
- वनों पर वैश्विक कार्रवाई के लिए एक रोडमैप है।
- यह वनों की कटाई और वन क्षति को रोकने के उद्देश्य से सभी वनों और पेड़ों के स्थायी प्रबंधन के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार करता है।

- इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि वन संरक्षण प्रयास सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक लक्ष्यों में योगदान करते हैं।
- UNSPF वनों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझेदारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो बेहतर सहयोग और संयुक्त कार्रवाई को बढ़ावा देता है।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. डिजीलॉकर क्या है और क्या यह आपके डेटा और दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखता है? - हिन्दू

प्रासंगिकता: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
सन्दर्भ:

- डिजीलॉकर 2015 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक ऐप के रूप में काम करता है।
- यह ऐप भारत सरकार की **पेपर लेस पहल** का हिस्सा है, जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल वॉलेट में आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंचने, सत्यापित करने और संग्रहीत करने की सुविधा देता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः प्राप्त करना और अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना आसान हो।
  - ऐप में **270 मिलियन** से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जबकि आधार, बीमा पॉलिसी कागजात, पैन रिकॉर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे **लगभग 6.7 बिलियन दस्तावेज़** इसके माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016** के **नियम 9ए** के अनुसार डिजीलॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेज़ मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माने जाते हैं।

डिजिलॉकर कितना सुरक्षित है?

- डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY)** की एक प्रमुख पहल है।
- डिजीलॉकर की वेबसाइट के अनुसार, इसमें निम्न मानक सुरक्षा उपाय हैं जैसे:
  - SSL (Secure Sockets Layer) एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (ओटीपी सत्यापन), सहमति प्रणाली, समयबद्ध लॉग आउट और सुरक्षा ऑडिट।
- हालाँकि, कोई भी सरकारी डेटाबेस जो नागरिकों की जानकारी और दस्तावेजों को संग्रहीत करता है, अनिवार्य रूप से हैकर्स के लिए एक आकर्षक लक्ष्य है जो उपयोगकर्ता डेटा चुराते हैं और इसे डार्क वेब पर बेचते हैं।
  - वर्ष 2020 में, डिजिलॉकर ने **"साइन-अप प्रवाह में संभावित भेद्यता"** के बारे में एक नोटिस पोस्ट किया, जिसके कारण खातों से छेड़छाड़ हो सकती थी।
  - हालाँकि, **CERT-In** अलर्ट के कारण, DigiLocker ने कहा कि अलर्ट मिलने के एक दिन के भीतर भेद्यता को ठीक कर लिया गया था, और उपयोगकर्ताओं के डेटा सुरक्षित था।
- **Google ने कहा कि**, कोई भी डिजिलॉकर डेटा तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ साझा नहीं किया जाता है और डेटा ट्रांज़िट में एन्क्रिप्ट किया जाता है।

डिजिलॉकर से जुड़ी समस्याएं:

- जो लोग स्मार्टफोन चलाने के शौक़ीन नहीं हैं या जिन्हें ऐप्स नेविगेट करने में कठिनाई होती है, उन्हें सहायता के बिना डिजीलॉकर डाउनलोड करने में कठिनाई हो सकती है।
- एक अन्य बाधा यह है कि कई नाम, उपनाम, असंगत वर्तनी, या यहां तक कि थोड़ा बेमेल प्रमाणपत्र वाले लोग डिजिलॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेज़ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- साथ ही, भारत में विभिन्न सरकारी प्राधिकरण और कानून प्रवर्तन निकाय आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा कैसे करते हैं, इसमें एकरूपता का अभाव है।
  - जबकि कुछ लोग डिजिलॉकर के माध्यम से वर्चुअल दस्तावेज़ दिखाए जाने पर जोर देते हैं, अन्य का दावा है कि मूल हार्ड कॉपी अनिवार्य है।

10. भारत- EFTA व्यापार सौदे से निवेश का सबक - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है या भारत के हितों को प्रभावित करता है।

समाचार:

- भारत ने **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)** के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया।

सन्दर्भ:

- भारत और EFTA के बीच **नवनिर्मित व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते** से दोनों पक्षों के बीच मौजूदा व्यापार के निम्न स्तर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- भारत और EFTA के बीच **FTA** इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को शामिल करने पर सहमत हुआ है, जिन्हें वह पारंपरिक रूप से व्यापार समझौतों में शामिल करने का विरोध करता रहा है।

विस्तृत निवेश	**आगे बढ़ने का रास्ता:**

• विस्तृत निवेश अध्याय एक अन्य कारण जो इस एफटीए को भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए से अलग करता है, वस्तुतः यह निवेश सुविधा के मुद्दों पर केंद्रित है, न कि निवेश सुरक्षा पर;
• इसकी एक उल्लेखनीय और अभूतपूर्व विशेषता है जिसमे भारत ईएफटीए देशों से यह वादा हासिल करने में कामयाब रहा है कि उनका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना होगा।
• साथ ही **निवेश अध्याय के अनुच्छेद 7.1(3)(बी)** में प्रावधान है कि EFTA राज्यों का लक्ष्य भारत में दस लाख नौकरियों के सृजन को सुविधाजनक बनाना होगा।
• **कानूनी शब्दावली में**, ये लेख **आचरण के दायित्व के रूप** में जाना जाता है, जो कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ईमानदार प्रयास करने का दायित्व, परिणाम या परिणाम के बावजूद, संहिताबद्ध करते हैं।
	• यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्तर गिर गया है।
	• भारत को एक स्पष्ट FTA नीति की जरूरत है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश कानूनों से निपटने में।
	• इसकी FTA नीति में दो महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए जाने चाहिए यथा-
	  ○ **सबसे पहले,** भारत को एक व्यापक आर्थिक संधि के हिस्से के रूप में व्यापार और निवेश पर बातचीत करनी चाहिए।
	  ○ **दूसरा,** भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक प्रभावशाली विवाद निपटान तंत्र के साथ, निवेश के मुद्दों के दायरे को केवल सुविधा से प्रभावी सुरक्षा तक विस्तारित करने पर विचार करना चाहिए।
	• इससे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी निवेशकों को प्रवर्तनीय कानूनी सुरक्षा प्रदान करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

फैक्ट फटाफट

1. अरोरा

- अरोरा अनिवार्य रूप से प्राकृतिक रोशनी हैं जो रात में चमकीले, घूमते हुए पर्दों के रूप में दिखाई देती हैं और नीले, लाल, पीले, हरे और नारंगी सहित कई रंगों में देखी जा सकती हैं।
- ये रोशनी मुख्य रूप से पूरे वर्ष उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के ध्रुवों के पास दिखाई देती हैं लेकिन कभी-कभी ये निचले अक्षांशों तक फैल जाती हैं।
- इन्हें उत्तर में ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है और दक्षिण में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है।

2. डेडबॉट्स

- इन्हें ग्रिफ़बॉट्स के रूप में भी जाना जाता है, ये दिवंगत प्रियजनों के एआई-सक्षम डिजिटल प्रत्यक्षीकरण हैं।
- ये चैटबॉट अपने डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और यहां तक कि वॉयस रिकॉर्डिंग का उपयोग करके उनके भाषा पैटर्न और व्यक्तित्व लक्षणों का अनुकरण करते हैं, ताकि एक वार्तालाप-एआई बनाया जा सके जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है।
- शोधकर्ताओं ने सचेत भी किया है कि ये चैटबॉट संभावित रूप से आरामदायक तो हैं, लेकिन अगर इन्हें सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया तो ये मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकते हैं

3. कावासाकी रोग

- कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय स्थिति है
- लक्षण- तेज बुखार, दाने, हाथों और पैरों की सूजन, आंखों के सफेद भाग में जलन और लाल होना, गर्दन में सूजी हुई लसीका ग्रंथियां और मुंह, होंठ और गले में जलन और सूजन।
- यह आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है।
- यह बच्चों में हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है।
- यह स्थिति प्रतिरक्षा प्रणाली को रक्त वाहिकाओं पर हमला करने का कारण बनती है, जो सूज जाती हैं।
- यह कोरोनरी धमनियों को प्रभावित करता है, जो हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाती हैं।
- यह बच्चे के लसीका ग्रंथि, त्वचा और मुंह, नाक और गले की परत में भी समस्याएं पैदा कर सकता है।

4. सशस्त्र बलों का रंगमंचीकरण

- यह एक अवधारणा है जो युद्धों और संचालन के लिए अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए तीन सेवाओं - सेना, वायु सेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करने का प्रयास करती है।
- तीनों सेवाओं के संसाधनों को एकीकृत करके एक थिएटर कमांड/यूनिट बनाया जाएगा।
- सामान्य अर्थ में, एक थिएटर कमांड एक एकल, एकीकृत कमांड संरचना के तहत तीन सेवाओं के संसाधनों को तैनात करता है।
- प्रत्येक कमांड को परिचालन भूमिकाओं के लिए एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र सौंपा गया है।
- वस्तुतः चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लगभग सभी प्रमुख देश थिएटर कमांड अवधारणा पर काम करते हैं

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्य भारत, चीन और रूस हैं-

1. जी-20
2. शंघाई सहयोग संगठन
3. बीआरआईसी
4. आईबीएसए
5. जी-7

नीचे दिए गए सही उत्तर कोड का चयन करें:

A. केवल 1, 2 और 3
B. केवल 2, 3 और 4
C. केवल 1, 2 और 4
D. केवल 3, 4 और 5

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: CDS 2019 को नरेश चंद्र की अध्यक्षता वाली रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था

कथन 2: उनका मुख्य कार्य भारतीय सेना की तीन सेवा शाखाओं के बीच अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना होगा

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q3. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है
2. यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा।
3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वीवीपी के बीच अधिव्यापित होगा

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q4. लिथियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक लचीली, सफेद-चांदी क्षार धातु है।
2. यह सबसे सघन धातुओं में से एक है
3. आयन के रूप में घुलनशीलता के कारण यह समुद्र के पानी में मौजूद होता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q5. भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन:

1. उनमें से कोई भी समुद्री जल का उपयोग नहीं करता है।
2. इनमें से कोई भी पानी की कमी वाले जिलों में स्थापित नहीं किया गया है।
3. उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q6. वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संरक्षित वनों में आरक्षित वनों की तुलना में अधिक सुरक्षा होती है
2. बांस एक लघु वन उपज है।
3. वनवासियों को वन क्षेत्र में उगे बांस को काटने का अधिकार है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q7. रैट होल खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह खनन का एक खतरनाक तरीका है, जिसमें छोटी सुरंगें खोदना शामिल है।
2. कोयला खनन की यह तकनीक आम तौर पर दक्षिणी राज्यों में प्रचलित है
3. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q8. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) द्वारा की गई थी।
2. इसका प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय जल में खनिज संसाधनों की खोज और दोहन को विनियमित करना है।
3. भारत आईएसए का सदस्य नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q9. डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है
2. इसमें एसएसएल एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण जैसे मानक सुरक्षा उपाय हैं।
3. डिजी लॉकर डेटा को तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ साझा किया जाता है

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q10. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह यूरोपीय संघ के सदस्यों का एक अंतरसरकारी संगठन है
2. इसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी।
3. इसका उद्देश्य अपने सदस्य राज्यों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है

स्पष्टीकरण

- **G20 के सदस्य:** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य
- **G7 के सदस्य:** कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **SCO के सदस्य:** भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य।
- **BRICS के सदस्य:** ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- **IBSA के सदस्य:** भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका।

उत्तर : 2 विकल्प D सही है

स्पष्टीकरण:

- **वर्ष 2012** में, नरेश चंद्र समिति ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की
- अंततः लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर की अध्यक्षता वाली रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों पर **वर्ष 2019** में सीडीएस का पद सृजित किया गया। **कथन 1 गलत है**.
- उनका मुख्य कार्य भारतीय सेना की तीन सेवा शाखाओं के बीच अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना और अंतर-सेवा संघर्ष को न्यूनतम रखना होगा। **कथन 2 सही है.**

उत्तर : 3 विकल्प A सही है

स्पष्टीकरण:

- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लक्ष्य मिशन मोड में और बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से चयनित गांवों का व्यापक विकास करना है।
- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2022-23 (2025-26 तक) में** उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए की गई थी, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। **कथन 1 गलत है.**
- यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा। **कथन 2 सही है.**
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप नहीं होगा। **कथन 3 ग़लत है.**

उत्तर : 4 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- यह एक नाजुक, सफेद-चांदी क्षार धातु है। **कथन 1 सही है.**
- यह विशिष्ट परिस्थितियों में सबसे कम सघन धातु और सबसे कम सघन ठोस तत्व है। **कथन 2 गलत है.**
- आयन के रूप में इसकी घुलनशीलता के कारण, यह समुद्र के पानी में मौजूद होता है और आमतौर पर लवणयुक्त पानी से प्राप्त होता है। **कथन 3 सही है.**

उत्तर : 5 विकल्प D सही है

स्पष्टीकरण

- **मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट** एक शीतलन जल प्रणाली का उपयोग करता है जो समुद्री जल का उपयोग करता है। समुद्री जल कच्छ की खाड़ी से निकाला जाता है। इसके अलावा, **रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र** से शुद्ध समुद्री जल का उपयोग विभिन्न पूरक प्रणालियों द्वारा किया जाता है। **कथन 1 गलत है**
- **WRI (वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) के शोध के अनुसार**, भारत के **40 प्रतिशत** थर्मल पावर प्लांट महत्वपूर्ण जल तनाव वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। यह एक चुनौती है क्योंकि ये पौधे शीतलन उद्देश्यों के लिए पानी पर निर्भर हैं। **कथन 2 गलत है**
- भारत में **कुल 269 थर्मल पावर प्लांट** हैं, जिनमें से **138 सार्वजनिक क्षेत्र** के स्वामित्व में हैं और **शेष 131 निजी क्षेत्र** के स्वामित्व में हैं। **कथन 3 ग़लत है**

उत्तर : 6 विकल्प A सही है

स्पष्टीकरण:

- आरक्षित वनों में संरक्षित वनों की तुलना में अधिक सुरक्षा है **कथन 1 गलत है**
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक **वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006,** बांस को लघु वन उपज के रूप में मान्यता देता है, **कथन 2 सही है**
- वनवासियों को गैर वन क्षेत्रों में उगे बांस को काटने का अधिकार है। **कथन 3 ग़लत है.**

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

उत्तर : 7 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- रैट-होल खनन खनन की एक गैर-कानूनी विधि है, जिसमें कोयला निकालने के लिए छोटी-छोटी सुरंगें खोदना शामिल है, जो इतनी बड़ी होती हैं कि कोई व्यक्ति उसमें से रेंगकर निकल सकता है। **कथन 1 सही है.**
- इस खनन की प्रथा आम तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों, **विशेषकर मेघालय** में प्रचलित है। **कथन 2 गलत है.**
- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)** ने इससे उत्पन्न विभिन्न चिंताओं के कारण **वर्ष 2014** में मेघालय में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। **कथन 3 सही है.**

उत्तर : 8 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है**. अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) की स्थापना **वर्ष 1982** में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत की गई थी।
- यूएनसीएलओएस एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो समुद्र और महासागरों से संबंधित सभी मामलों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करती है।
- **कथन 2 सही है.** ISA एक अंतरसरकारी संगठन है जो उस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और दोहन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे समुद्र तल और महासागर तल है।
- इसमें पॉलीमेटैलिक नोड्यूल, कोबाल्ट क्रस्ट और सल्फाइड जैसे संसाधन शामिल हैं।
- **कथन 3 ग़लत है**. भारत अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण का सदस्य है।
- वास्तव में, भारत **वर्ष 1987** में **"अग्रणी निवेशक"** का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था, जिसने इसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के विकास के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन में समुद्र तल के एक विशिष्ट क्षेत्र का पता लगाने का विशेष अधिकार दिया था।

उत्तर : 9 विकल्प A सही है

स्पष्टीकरण:

- डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है। **कथन 1 गलत है.**
- डिजीलॉकर की वेबसाइट के अनुसार, इसमें मानक सुरक्षा उपाय हैं जैसे:- SSL एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (ओटीपी सत्यापन), सहमति प्रणाली, समयबद्ध लॉग आउट और सुरक्षा ऑडिट। **कथन 2 सही है.**
- **Google ने कहा**, कोई भी डिजिलॉकर डेटा तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ साझा नहीं किया जाता है और डेटा ट्रांज़िट में एन्क्रिप्ट किया जाता है। **कथन 3 ग़लत है.**

उत्तर : 10 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- **EFTA-** आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है
- ये चारों देश EU (यूरोपीय संघ) का हिस्सा नहीं हैं. **कथन 1 गलत है.**
- **स्थापना- वर्ष 1960** में **स्टॉकहोम कन्वेंशन** द्वारा की गई थी। **कथन 2 सही है।**
- **उद्देश्य-** अपने चार सदस्य देशों और दुनिया भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। **कथन 3 सही है.**

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com